अगर आप मेहनत करना जानते है तो उसके बल पर पाने की इच्छा भी रख सकते है।
– अज्ञात

बात जल्दी समझ में आ गई

अपनी पार्टी शिवसेना के पारंपरिक मुहावरों और कार्यशैली को एक तरफ रखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों में भरोसा पैदा करने के व्यक्तिगत प्रयास किए हैं।

रानी जोशी।

महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देने वाली जो बयानबाजी पिछले एक–दो दिनों में कई दिशाओं से हुई है, वह बेहद चिंताजनक है। गनीमत है कि नेताओं को बात जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने समय से अपने जुबानी घोड़ों की लगाम खींच ली। कोरोना से लड़ाई पूरे देश में चल रही है लेकिन महाराष्ट्र इसका सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है।

पूरे देश के कुल संक्रमितों का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा यहीं है और औद्योगिक रूप से यह देश का सबसे अग्रणी राज्य भी है। जाहिर है, कोरोना वायरस को निर्णायक रूप से शिकस्त देने की बात हो या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से आई मंदी के दुष्चक्र से निकालने की, कांटा आखिरी तौर पर वहीं जाकर ठहरता है।

महाराष्ट्र उबरेगा तभी राष्ट्र के उबरने की संभावना बनेगी। राहत की बात कोई है तो यही कि महाराष्ट्र की सरकारी मशीनरी अपने काम की अहमियत को समझते हुए पूरी शिद्दत से यह लड़ाई लड़ रही है। अपनी पार्टी शिवसेना के पारंपरिक मुहावरों और कार्यशैली को एक तरफ रखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों में भरोसा पैदा करने के व्यक्तिगत प्रयास किए हैं।

संसाधनों की सीमाओं के बावजूद कोरोना से लड़ाई में स्थितियां बेहतर हुई हैं। पिछले दो महीने की मशक्कत के बल पर संक्रमण के मामले दोगुने होने की अवधि को तीन दिन से बढ़ाकर 14 दिन पर ला दिया गया है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर अप्रैल में 7.6 फीसदी थी जो अब 3. 25 फीसदी रह गई है। तात्पर्य यह नहीं कि प्रदेश में कोरोना की चुनौती कमजोर पड़ गई है या राज्य मुसीबत से बाहर आ चुका है। ऐसी संभावना अभी दूर की चीज है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार और सरकारी तंत्र पूरी ताकत से जूझ रहे हैं और एक–एक इंच करके ही सही, आगे बढ़ रहे हैं।

महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने बीमारी को सामने से घेरने के लिए 'चेज द वायरस' कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत न केवल जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है बल्कि कम्यूनिटी लीडर्स बहाल करके संभावित मरीजों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक गौरतलब बात यह भी है कि देश में कोरोना महामारी को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिशें चलती रहीं और कई राज्यों में वे कामयाब भी रहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये बिल्कुल रफ्तार नहीं पकड़ पाईं।

पिछले तीन–चार दशकों के इतिहास को देखते हुए यह खुद में एक सुखद आश्चर्य है। लेकिन बीच–बीच में उतावलापन दिखा रहे सत्ता पक्ष के सभी घटक दलों और साथ ही विपक्ष को भी यह याद रखना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता का हल्का सा झोंका भी उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। सत्ताधारी गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी स्वयं में एक जटिल राजनीतिक प्रयोग है, लेकिन इस असाधारण चुनौती के सामने अगर वह कामयाब होकर उभरता है तो इससे पूरे देश में वैकल्पिक राजनीति के कुछ बंद दरवाजे खुल जाएंगे।

अपना दोस्त

अशोक वोहरा।

इस अवस्था में मुझे मालूम है कि मैं खुद अपना दोस्त हूं। मैं मौन हूँ, एक दम शांत। यह शांति का गहरा कुआं ही आत्मा की मूल अवस्था है। जब मैं उस स्थिति में होती हूं, मैं मानवता के लिए प्यार का प्रवाह महसूस करती हूं, मैं एक ऐसी अवस्था महसूस करती हूं जिसे मैं खुशी से ज्यादा मानती हूं, आनंद की स्थिति। इस अवस्था को हासिल करके सच में कुछ चमत्कार जैसा हो सकता है। जब मैं पूर्ण आत्मा–चेतना की स्थिति में होती हूं, मुझे यह पता होता है कि मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह शुरू होने वाला है। मुझे इतनी व्यापक शक्ति महसूस होती है कि इस क्षण में मैं जानती हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं पहुंच सकती। जब ऐसा होता है, मैं दैवीय ऊर्जा के साथ संबंध महसूस करती हूं और मुझे लगता है ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर आ रही है।

संपादकीय

फाके करने की नौबत

अचानक लगे लॉकडाउन में श्रमिकों के ऊपर ही नहीं, देश के कोने–कोने में फैले दो करोड़ छोटे और मंझोले दुकानदारों पर भी पहाड़ टूटा है। इनकी दुकानों से करीब दस करोड़ लोगों के परिवार भी चलते हैं। लॉकडाउन के चलते इनके फाके करने की नौबत आ चुकी है। व्यापारियों के इस वर्ग में नुक्कड़ पर चलने वाली दुकानों से लेकर सालाना पांच करोड़ के टर्नओवर वाले व्यापारी हैं। इनके व्यापार का आधार रोजाना बिक्री के बदले चेक या कैश में मिले धन का सर्कुलेशन है, जिससे पुराना उधार चुकता होता है और नया माल आता है। आम तौर पर इनकी 20 से 40 फीसद पूंजी पर्सनल या बैंकों के लोन की होती है, जिस पर इन्हें 12 से 20 प्रतिशत तक का ब्याज देना होता है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद इन्हें अगर हफ्ते भर का भी वक्त मिल जाता तो जल्दी खराब होने वाली चीजों को या तो हटा लिया जाता या सस्ते में बेच दिया जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते पान–तंबाकू, बेकरी के सामान, ढाबे, मिठाइयां व नमकीन आदि की दुकानों का कच्चा–पक्का सब माल नष्ट हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर कई हजार करोड़ की स्टॉक की बर्बादी हुई जो पूंजी की सीधी क्षति है। बंद पड़ी दुकानों में दीमक और फंगस से भी खूब स्टॉक बर्बाद हुआ। पिछले दस सालों में देखें तो हर राजनीतिक पार्टी ने अपने ध्रुवीकरण के लिए इन व्यापारियों का जमकर इस्तेमाल किया है, इसलिए व्यापारियों का बहुसंख्यक वर्ग यह मानकर चल रहा था कि उनको केंद्र सरकार उपेक्षित नहीं रखेगी। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जीडीपी में 10 प्रतिशत का सहयोग करने वाला व्यापारी वर्ग इस बार यह मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वह खुद हेल्पलेस है।

प्रदेश में नीतीश को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वैसे तो नाराजगी सरकार से है, लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते लोगों का सारा गुस्सा नीतीश पर है। बीजेपी के प्रति गुस्सा कम है।

सारा गुस्सा नीतीश पर

शिवेंद्र कुमार

बिहार में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अंदरखाने सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी अगले सप्ताह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक वर्चुअल रैली भी करने जा रही है। यह बिहार में अपने तरह की पहली रैली होगी। उसकी तैयारियां जोरो–शोरों से चल रही है। दूसरी तरफ आरजेडी ने चुनाव नजदीक देखते अपने कोर वोटरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी धीरे–धीरे ही सही लेकिन अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन, वास्तव में चुनाव अगस्त–सितंबर में होने वाले कोरोना के कहर से पर निर्भर है। अगर देश के साथ–साथ बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो चुनाव टल सकता है। एक्सपर्ट कह भी रहे हैं कि जुलाई–अगस्त में महामारी भयंकर रूप दिखा सकती है। ऐसे में दो विकल्प हैं। पहला, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए या दूसरा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को रखते हुए सरकार को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। ये दोनों ऑप्शन केंद्र सरकार के हाथ में हैं। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी के लिए पहला विकल्प ही बेहतर रहेगा।

यह सब चीजें तो कोरोना के कहर पर निर्भर करेंगी, लेकिन नीतीश के मन में जो अंदरखाने सुगबुगाहट चल रही है, उसे समझने की जरूरत है। करीब 15 सालों नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ वह मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। लेकिन, अब स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश में नीतीश को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वैसे तो नाराजगी सरकार से है, लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते लोगों का सारा गुस्सा नीतीश पर है। बीजेपी के प्रति गुस्सा कम है।

2014 और 2019 के आम चुनाव की तुलना में 2024 के चुनाव का माहौल भी बदला हुआ नजर आ रहा है। केंद्र की राजनीति में नीतीश प्रभावी ढंग से अपनी मौजूदगी चाह रहे हैं। नीतीश का यह सपना भी रहा है। उन्हें अपने सपने को पूरा करने का माहौल भी बनता दिखाई दे रहा है। गैरबीजेपी खेमे में कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में नीतीश कुमार दिख भी रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो नीतीश के विश्वस्त विपक्षी खेमे में उनकी भूमिका के लिए जगह बनाने के काम में लग गए हैं। नीतीश को लगता है कि ऐसी स्थिति में एक गैरबीजेपी गठबंधन बनता है तो उन्हें नेता के रूप में स्वीकार्य किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता की तुलना में उनकी साफ–सुथरी छवि इसमें मददगार साबित हो सकती है। साथ ही जाति इस देश की राजनीति के केंद्र में है और पिछड़ा होने के नाते नीतीश भी उस गणित में फिट बैठते हैं। खासकर मध्य और उत्तर भारत की राजनीति के लिए तो वह बिल्कुल फिट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछड़ा काट को अगर कोई काट सकता है तो वह हैं नीतीश हैं।

अब सवाल उठता है कि इतने समीकरण बन रहे हैं तो दिक्कत कहां है। वास्तव में दिक्कत खुद नीतीश कुमार हैं। वह जानते हैं कि 2024 के चुनाव में अभी समय है।

अष्टयोग-5072

3		4		7		2
	33		34		30	
5		7	1	2		4
4	30		25		34	
1		3		5	6	
	36		34		31	3
	6	5	4		2	1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

अष्टयोग 5071 का हल

3	5	4	6	7	1	2
2	33	1	36	6	27	5
7	6	5	4	3	2	1
4	30	2	27	1	31	6
1	2	3	4	5	6	7
6	36	6	32	4	34	3
5	6	7	1	2	3	4

अपना ब्लॉग

अन्य विशेषज्ञों की काफी कमी

मोहन। राजद का कहना है कि वह नीतीश को केंद्र में नेता मानने को तैयार हो सकते हैं लेकिन उन्हें बिहार में अपनी दावेदारी छोड़नी होगी। तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश और उनकी पार्टी बिहार में नंबर दो की भूमिका में आए। यही बात सबसे बड़ी बाधा बन रही है। नीतीश को यह स्वीकार नहीं है। वह जानते हैं कि राजद को पता है कि वह अकेले बिहार में सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। राजद को हर कीमत पर सत्ता के लिए जेडीयू की जरूरत है। नीतीश को लगता है कि आरजेडी उनकी ताकत बन जाएगी और अंत में तेजस्वी उन्हें केंद्र और राज्य, दोनों जगह नेता मानने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखना है कि चुनाव से पहले इस बार नीतीश पलटी मारते हैं या नहीं? वह चाहते हैं कि विपक्षी खेमा केंद्र में मुझे पीएम का चेहरा तो बनाए ही, साथ ही राज्य में भी तब तक मुख्यमंत्री मुझे ही रहने दे। नीतीश का यह शर्त राजद के नए नेतृत्व तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं है।